



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226475  
CG-DL-E-09042021-226475

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1432]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 1432]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

**का.आ. 1543(अ).**—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 3) द्वारा यथा संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 4 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संहिता के अध्याय-3 के अधीन निगमित ऋणी पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित मामलों के लिए व्यतिक्रम की न्यूनतम रकम के रूप में दस लाख रुपए को विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं.30/20/2020-इंसोल्वेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

**S.O. 1543(E).**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 4 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), as amended by the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021 (3 of 2021), the Central Government hereby specifies ten lakh rupees as the minimum amount of default for the matters relating to the pre-packaged insolvency resolution process of corporate debtor under Chapter III-A of the Code.

[F. No. 30/20/2020-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.